है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक 9-2-87 को हुई थी।

इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षक के रूप में किसी गैर-सरकारी सदस्य को नामित नहीं किया गया है । तथापि, कुछेक अधीनस्थ कार्यालयों ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षकों के रूप में हिन्दी सलाहकार समिति के स्थानीय सदस्यों को नामित किया है। इस मुद्दे पर और प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

433. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) चालू वर्ष के दौरान अब तक रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य, रेलवे बोर्ड कार्यालय और क्षेत्रीय/उत्पादन कारखानों आदि की प्रधान कार्यालय स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पहले से ही प्रेक्षक सदस्य के रूप में नामित हैं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

434. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से संबद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किये जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुये 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किये 10 वर्ष हो चुके हैं ?